

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निर्यातक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 24 मई 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

बिगडैल बाप के बेटे और कानून

पुणे में अमीर बाप के बिगडैल अल्पवयस्क बेटे ने शराब के नशे में दो युवा इंजीनियरों को रॉडने के बाद जिस तरह आनन-फानन में जमानत हासिल की, उस घटना ने तमाम सवाल को भी जन्म दिया। दुस्साहस देखिये कि दो करोड़ रुपये से अधिक महंगी विदेशी कार को सड़क पर यह किशोर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। उस धनी बाप के नशेड़ी बेटे को पुणे की सड़कों में रोकने वाला कोई नहीं था। उसने कई जगह दोस्तों के साथ शराब पार्टियां निबटाने के बाद अपनी पोर्श कार को इतनी अनियंत्रित गति से दौड़ा कि मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को मोत की नौदल दिया। संयोग से दोनों इंजीनियर जबलपुर, मध्यप्रदेश की थे ही। इस मामले में सोशल मीडिया पर आक्रोश का लावा तब फूटा जब 17 साल कुछ महीनों की उम्र वाले अभियुक्त को किशोर होने के नाते कुछ ही घंटों में जमानत दे दी गई। दो परिवारों के उम्मीदों के चिराग बुझ गए और किशोर न्यायालय ने अभियुक्त को कुछ निर्देश देकर ही छोड़ दिया।

सोशल मीडिया पर यह विषय रोष का विषय बना रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत देते वक्त उसे महज दुर्घटना पर निबंध लिखने, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने तथा मनोचिकित्सक को शराब की लत का इलाज कराने को कहा। इन शर्तों को सुनकर सोशल मीडिया पर गंभीर अपराधों में लिप्त किशोरों को वयस्क की तरह दंड देने की मांग तेज हुई। फिर जब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई तो अभियुक्त किशोर के अरबपति बिल्डर पिता और नाबालिगों को शराब परोसने वाले होटल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक जागरूकता की पहल रंग लायी और चुनावी माहौल में तुरत-फुरत कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देश से लोगों में सकारात्मक संदेश गया। साथ ही पीडित पक्ष में भी विश्वास जगा कि कानून काम करता है चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। निस्संदेह, ऐसे मामलों में अभियुक्तों के साथ शून्य सहिष्णुता का संदेश जाना ही चाहिए।

बहरहाल, इस घातक दुर्घटना के बाद सार्वजनिक निमर्श में यह सवाल फिर उठा कि गंभीर अपराधों में किशोरों की सिलपता होने पर वयस्क के कानून के हिसाब से उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती। सवाल यह है कि घनाढ्य बिल्डर ने क्यों किशोर पुत्र को बिना लाइसेंस के कार चलाने की अनुमति दी? क्यों बेटे को शराब पार्टी करने की इजाजत दी? क्यों होटल वालों ने किशोरों को शराब पीने की सुविधा दी? जब किशोर ने बार-बार जानबूझकर तमाम कानूनों का उल्लंघन किया तो उसे सामान्य कानून के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बहरहाल नये सिर से किशोर न्याय अधिनियम में सुधार की बहस तेज हुई। एक गंभीर आपराधिक घटना के बाद किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर को मामूली परामर्श के बाद छोड़ना भी विवाद का विषय बना। सामाजिक व राजनीतिक दबाव के बाद पुणे पुलिस द्वारा की गई तुरत कार्रवाई समय की जरूरत थी। जो कालांतर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टालने में मददगार हो सकती है। कहा जाने लगा कि अपराध के अनुपात में दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। दरअसल, देश के विभिन्न भागों में भी किशोरों द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने के तमाम मामले प्रकाश में आते रहते हैं, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग के चलते कई किशोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये घटनाएं शायदात कानूनों को सख्ती से लागू करने और किशोर अपराधियों को दंडित करने के लिये कानूनी ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती हैं। निस्संदेह, देश की न्यायिक प्रणाली को इस तरह के मामलों में उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सही मायनों में अपराधी की उम्र की परवाह किये बिना ऐसे घातक कृत्यों में कड़े दंड के जरिये मिसाल कायम की जानी चाहिए। इससे जहां जनता का विश्वास बहाल होगा, वहीं हमारी सड़कों पर किशोरों की लापरवाह ड्राइविंग से होने वाली मौतों को भी रोका जा सकेगा। निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं में मारे लोगों के परिजनों को भी न्याय मिल सकेगा।

किस करवट बैटेगा पूर्वांचल का सियासी मिजाज



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश में पांच चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक ताकतों का पूरा फोकस पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों पर आकर टिक गया है। पूर्वांचल में पूरे प्रदेश से अलग सियासी बयार बहती है। यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी संशक भीर है। यहां के लोगों की रंग-रंग में सियासत देखने को मिल जाती है। तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को भी पूर्वांचल की धरती काफी रस आती है। यहां से निकले नेताओं ने देश-विदेश में खूब नाम कमाया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों में पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चन्द्रशेखर यहीं की धरती से निकलकर सियासत की दुनिया में परचे थे। पूर्वांचल से सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाले सांसदों की सूची पर नजर डालें तो बलिया की धरती के रहने वाले देश के पूर्व प्रान्तीय चंद्रशेखर 1977 से 1991 तक के बीच में बलिया से रिकार्ड 8 बार संसद निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा बलिया के चंद्रशेखर सिंह को 8 सांसद से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। इन 27 सीटों में एक सीट वाराणसी की भी है, जहां से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यह उनका तीसरा लोकसभा चुनाव है। मोदी की जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। यहां तक की सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक



ने यहां से मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। हां, यह और बात है कि वह यहां से तीसरी बार चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री के रूप में भी हिट्टिक लोग पायेंगे। इस बार यहीं मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के लगातार तीन कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। इसके अलावा वीजेपी के नेता पूर्वी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, लेकिन सिया को यही लगता है कि अबकी से मोदी बुरी तरह से हार रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आया जाय तो पूर्वांचल ने देश को देश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपालानी जैसी नेत्री दी तो संपूर्णदल, कमलावती त्रिपाठी, वीर बहादुर सिंह और वन नरेश यादव जैसे मुख्यमंत्री यूपी को दिए। इतना ही नहीं सीपीएम सिंह, महावीर

प्रसाद, कल्याण राय, सुखदेव प्रसाद, केडी मालवीय, आरपीएन सिंह और कलजि मिश्र जैसे नेता पूर्वांचल से कांग्रेस को एक और कांग्रेस के पांच सीटें मिली हैं। इन सीटों को पर कांग्रेस और सपा ने फटल संघर्षों के पश्चात्कारियों को उतार दिया है। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों पर एक-एक टिक का हिसाब रखा जा रहा है।

यूपी के परिचयी, मध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में चुनाव होने के बाद सभी दलों के आलाकमान ने यहां के ज्यादातर नेताओं को इन्हीं 27 सीटों पर उतार दिया गया है। माजपा ने वाराणसी में महिला सम्मेलन के जरिए नया प्रयोग किया है तो आसपास की सीटों पर प्रयाग का नाम मंडल अपनाया है। पार्टी की ओर से पूर्वांचल की सीटों पर जल जीवन मिशन, मकान और शौचालय

हित अन्य योजनाओं का काम पाने वाले लामार्थियों की ब्लॉकवार सूची निकाली गई है। इस सूची के जरिए मतदाताओं तक पहुंच कर उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हर विधानसभा को तीन से चार हिस्से में बांट कर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठकें की जा रही हैं। इतना ही नहीं पार्टी ने नई रणनीति के तहत समूह बैठक तय की है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कपड़ा कारोबारी, दवा व्यापारी की बैठकें तय की गई हैं। उदाहरण के लिए हिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत नेताओं को इसी क्षेत्र के लोगों से मिलने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए बलिया के महामंत्री सुभाष कुशवाहा ने बताया कि वाराणसी और आसपास की सीटों पर इटवा, एक, फर्रुखाबाद, मैथिली सहित सैकड़ों के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का विचार किया गया है। इसी तरह निपाद बहुल इलाकें में इसी विरादरी के नेताओं को जम्मेदारी देने पर जोर दिया है। ब्राह्मण बहुल इलाके की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने संभाली है। वह दिन में सपा-कांग्रेस के नेताओं के बीच सम्मन बैठकें कर रहे हैं तो रात में ब्राह्मण बहुल इलाकें में रात्रि चौपाल लगा रहे हैं। इसी तरह सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजपाल कश्यप निपाद, कश्यप, बिंद विरादरी के बीच रात्रिकौली बैठकें करने में जुटे हैं। डा. कश्यप का दावा है कि सपा की ओर से निपाद विरादरी के पांच प्रत्याशी उतारने का फायदा मिल रहा है।

छठे चरण की 14 सीटें पर सातह चरणी की 13 सीटें पर कई दिग्गज नेतृत्व में हैं। इसमें सुलतानपुर से मेतका भी हैं। आसपास से धर्म यादव, भदोही से सुभद्रलु कांग्रेस के ललितशशिपि मिश्रा, इलाहाबाद से उज्जवल रमण सिंह, जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गुमनामी कृपाशंकर सिंह जैसे नामचीन चेहरे हैं। बाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उन पर निगाह रखी जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अलग से टीम लगाई है। यह टीम नेताओं के कार्यक्रम और उनके द्वारा जनसभा में उठाए गए सवाल का जवाब तैयार कर अपने नेताओं को भेज रहा है। इतना ही नहीं अगले दो से तीन दिन में

संविधान की मूल भावना और आसपास की कसौटी



—के.पी. सिंह—

वर्तमान लोकसभा चुनावों के प्रारंभ में आसपास को लेकर, विश्वेश्वर एक समुदाय के आरक्षण पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि नतासिनी पार्टी यदि पुनः सरकार बनने में सफल हो गई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। वहीं सत्ता-पक्ष कुछ रायों में मूलभूतमान को दिए गए हैं और आरक्षण पर सवाल खड़ा करके उसे संविधान विरुद्ध बता रहा है। राजनीति को दरकिनार करके यदि देखा जाए तो आरक्षण ऐसी संविधान प्रदान गारंटी है जिसके सहारे एक समाजवादी और समावेशी समाज की परिकल्पना की गई थी। और यह तब तक प्रायोगिक रहेगा जब तक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमताएं और भेद-भाव जलित परिस्थितियां दूर नहीं होती। आरक्षण सम्बन्धी प्राधान्य संविधान में चार अलग-अलग स्थानों पर मौजूद है। अनुच्छेद 330 से 335 तक में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जात-जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्राधान्य हैं। एंनो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन और रजिस्टर तथा डाक विभाग में दस वर्षों तक आरक्षण का आभार भी इन्हीं अनुच्छेदों में है। यहां महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के लिए छुआ-छूत जलित भेदभाव, जनजातियों के भौगोलिक एक सांस्कृतिक अलगाव तथा एंनो-इंडियन समुदाय की सीमित संख्या उन्हे आरक्षण एवं मनोनयन का आधार प्रदान करती है। दूसरे, संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(4) एवं 15(6) में महिलाओं, वंचित, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में राखला पाने को आरक्षण दिया है। वर्ष 2019 में संविधान संशोधन कर आर्थिक पिछड़पन को मान्यता देकर इन वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।



आरक्षण की संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इंदिरा साहनी प्रकरण (1992) में न्यायालय द्वारा व्याख्या दी गयी थी कि पिछड़े वर्गों की 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो और 50 प्रतिशत से अधिक भी नहीं होना चाहिए। (1951) के दौरान केन्द्र विधु में आया, अदालत ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 15 में इसका विक्रम तक नहीं है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्राधान्य कर दिया गया। वर्ष 1953 में पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने के लिए पाला पिछड़ा वर्ग आयोग काकालेलेकर की अध्यक्षता में बनाया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट 1980 में लागू की गई थी। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट ई मुसम्मिलत को पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि दो प्रकार की मुसलमान जातियां पिछड़ी जाति माननी जांरगी, पलवी, डे जो भू भू परिवर्तन के लिए हिन्दू अडूत जातियां थीं और दूसरी, वे हिन्दू पिछड़ी जातियां जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपना परम्परागत

व्यवसाय जारी रखा हो। इसके बाद अनेक राज्यों ने मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियों को आरक्षण लाभ देना शुरू कर दिया था। आरक्षण की संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। इंदिरा साहनी प्रकरण (1992) में न्यायालय द्वारा व्याख्या दी गयी थी कि 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो और 50 प्रतिशत से अधिक भी नहीं होना चाहिए। इसके तुरन्त बाद संविधान संशोधन करने सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का आभार बरकरार रखा था। एक प्रकरण में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैरिट व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दस वर्ष उपरान्त आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए। संविधान में संवैधानिक की अर्क प्राण उन लोगों के मुख्य धारा में समावेश का आधार बना थी जो ऐतिहासिक अथवा अन्य कारणों से पीछे छूट गए थे। इसका अतिप्राय है, जो लोग पिछड़ेपन से बाहर आ गए हैं उन्हें आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि अन्य पात्र पिछड़े वर्ग के आसपास जा सकें। अतः आरक्षण की सामयिक समीक्षा जरूरी है परन्तु वोटकें राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आरक्षण संस्था की सकारात्मक उपायों की समन्वयी अक प्राणा का प्रतिबिम्ब है। इन नीतियों को संविधान की मूल भावना के आलोक में ही लागू किया जाय, न कि सिवाय ही। संविधान के एक तंत्र के रूप में लेखक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।

चीन से कारोबारी असंतुलन



—जयंतिलाल भंडारी—

यकीनन इस समय चीन से आयात बढ़ने से कारोबार असंतुलन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वस्तुओं के चीन से आयात को नियंत्रित करने के मंजूर शुरु की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के वावजूद नवंबर, 2023 में मार्च, 2024 के 6 महीनों में चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अरब डॉलर के निर्यातों के बावजूद भी चीन से लैपटॉप एवं टैबलेट सहित कंप्यूटरों की आवाक 47.1 प्रतिशत बढ़ गई है। इस अवधि में भारत ने चीन से 27.36 करोड़ डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात किए हैं। यद्यपि इन उत्पादों के लाभांतर और हानिकांश में भी आयात किए गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में चीन से आयात किए गए आयात का मूल्य कई गुना अधिक है। हाल ही में 17 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्योग वस्त्रों सीआरटी के सालाना वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जात को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। यह पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है और आयात में 44 फीसदी का इजाफा हो चुका है जबकि चीन को होने वाला निर्यात तत्करीबन स्थिर है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के वावजूद चीन से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर अतीव चिन्तित और चिन्तित मंत्री ने भारतीय उद्योग जात को भी आह्वान किया और सम्मेलन में उपरिष्ठ भारत के उद्योग जगत के संकेतों प्रतिक्रियाओं की तरफ चीन से हुई वृद्धि के मंजूरन इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि, क्या आप उद्योग संस्थ कारोबार करों को आपक ड्रॉग्न में घुसा कर आपका धर को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट की है कि उद्योगियों को राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संबन्धनों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि, रमेश चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संबन्धनीयता को भी ध्यान में रखा होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनायें, भारत में खरीदें। जो राष्ट्रीय हित में है वह लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अपनी जरूरतें हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें घरेलू सोर्सिंग व उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी आधार पर हमें फंसला करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.41 अर

